है, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूं, इस पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार हूं । जहां तक टारगेट या लक्ष्य निर्धारित करने का सवाल है । टूरिज्म डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो नीति निर्धारित कर सकता है और अपनी इच्छुकता व्यक्त कर सकता है । स्टेट गवर्नमेंट से चर्चा कर सकता है पर अंततोगत्वा मुख्य जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है क्योंकि लैंड, पावर, कंस्ट्रक्शन ये सब बातें स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं और कई बार हमको दिक्कतों और कठिनाइयों को महसूस करना पड़ता है अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को क्रियान्वित करने में, इसीलिए कोई टारगेट **(व्यवधान)**

श्री राम नरेश यादव : कब तक बात हो जाएगी क्योंकि मामला बहुत गम्भीर है।

श्री सभापति : ये कैसे बता सकते है ?

इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबन्ध

*342. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** :

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगाये जाने के कारण वहां दवाइयों और खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता के कारण लाखों बच्चे और वृद्ध व्यक्ति मर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को इस संबंध में लिखा है

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAV SINH SOLANKI) : (a) Government is aware of the serious situation within Iraq caused by UN economic sanctions against that country and the acute shortages of essential commodities, including food and medicines.

(b) Being alive to the humanitarian aspects of the situation, India has consistently advocated at the United Nations Security Council, easing of sanctions against Iraq, which would enable imports into Iraq of food, medicines and other essential commodities.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मोहतरिम चेयरमैन साहब, आपकी तवस्सुत से मैं वजीरे खारिजा से जो जवाब दिया है उसके बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ तवज्जह दिलाकर इनसे कुछ पूछना चाहता हूं । मोहतरिम वजीर ने जवाब दिया है कि हुकूमते हिंद इस बात से बाखबर है कि इराक के अंदर बूढ़े, जवान और बच्चे बीमारी से, दवाइयों की कमी से और खाने पीने की चीजों की कमी की वजह से मारे जा रहे हैं । सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर बराबर इस बात की कोशिश हुकूमते हिंद की तरफ से होती रही है कि वहां जो परेशानी है, इराक के अंदर, उसको कम करने की कोशिश की जाए और दवाइयां और खाने की चीजें वहां एक्सपोर्ट हो सकें या वहां तक पहुंच सकें । इसकी सरकार ने वकालत की है। मैं इसी संबंध में इसी ताल्लुक से मोहतरिम वजीर से यह पूछना चाहूंगा कि गुजिश्ता दो हफ्ते पहले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 51 मेम्बरान ने पार्लियामेंट ने एक मेमोरेंडम या एक एहतिजाजी खत यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को लिखा था । इसमें राज्य सभा और लोक सभा के 51 मेम्बरान ने पार्लियामेंट शामिल थे । इस पर दस्तखत करने वाली पार्टियों के नाम थे--जनता दल, सी०पी आई० "एम०", सी०पी०आई०, डी०एम०के०, समाजवादी जनता दल और भारतीय जनता पार्टी.. **(व्यवधान)** मैं यही सवाल कर रहा हूं कि इस खत को बी०बी०सी० ने नश्र किया, वाइस आफ अमेरिका ने नश्र किया, दूरदर्शन ने भी नश्र किया । क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है और अगर जानकारी है तो इस सिलसिले में मंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस को लिखित रूप में क्या कार्यवाही की है या क्या रिक्वेस्ट की है वह बताना गवारा करेंगे ? लिखित रूप में उन्होंने क्या काम किया है। चूंकि सवाल का जवाब दिया है कि यूनाइटेड नेशंस में

†सभा में यह प्रश्न श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल द्वारा पूछा गया ।

हमने इसकी वकालत की है । वकालत करना अलहिदा बात है । हमने किसी अखबार में पढ़ा नहीं कि हुकूमते हिंद ने इसकी वकालत की है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमते हिंद ने तहरीरी तौर पर यूनाइटेड नेशंस को कोई खत लिखा है या उस तरफ मुतवज्जह किया है कि इराक के जो बच्चे मर रहे हैं जो दवाइयां वगैर वहां सप्लाई नहीं हो रही हैं उनका इन्सानी बुनियाद के ऊपर फौरी तौर पर तदारुक होना चाहिए और वहां पर दवाइयां और खाना पीना, खास तौर पर बेबी मिल्क फूड जाना चाहिए। मैं आपके हवाले से यह भी बताना चाहता हूं कि इन्सानी हुकूक की बहुत सारी आर्गेनाइजेशंस ने इस सिलसिले में तवज्जह दिलाई है कि अगर फौरी तौर पर इराक में दवाइयां और बेबी मिल्क फूड नहीं भेजा गया तो एक साल के अंदर 1 लाख 70 हजार बच्चे मर जाएंगे और तकरीबन 1 हजार बच्चों की रोजाना मौत वहां वाकई हो रही है । तो यूनाइटेड नेशंस का क्या फर्ज है । क्या हुकूमते हिंद इस सिलसिले में कोई सख्त और तहरीरी कार्रवाही कर रही है ?

[illegible] मुहम्मद अफजल: محترم چیئرمین صاحب۔ آپ کے توسط سے میں وزیر خارجہ نے جو جواب دیا ہے۔ اس کے بہت سے اہم نکتے کی طرف توجہ دلا کر ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ محترم وزیر نے جواب دیا ہے کہ حکومت ہند اس بات سے باخبر ہے کہ عراق کے اندر بوڑھے، جوان اور بچے بیماری سے دواؤں کی کمی کی وجہ سے اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں۔ سرکار کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنس کے ذریعہ برابر اس بات کی کوشش حکومت ہند کی طرف سے ہوتی رہی ہے کہ وہاں پر [illegible]

ہے۔ عراق کے اندر اس کو کم کرنے کی کی جائے۔ اور دوائیوں اور کھانے کی چیز وہاں ایکسپورٹ ہو سکیں یا وہاں تک سکیں۔ اس کی سرکار نے وکالت کی ہے۔ میں اسی سمبندھ میں اسی تعلق سے محترم وزیر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گزشتہ ہفتہ پہلے ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ۵۱ ممبران پارلیمنٹ نے ایک میمورنڈم ایک احتجاجی خط یونائیٹڈ نیشنس سیکریٹری جنرل کو لکھا تھا۔ اس میں [illegible] اور لوک سبھا کے ۵۱ ممبران پارلیمنٹ شامل تھے۔ اس پر دستخط کرنے والی پارٹیوں کے نام تھے جنتا دل۔ سی۔ پی۔ آئی۔ "ایم" سی۔ پی۔ آئی۔ ڈی۔ ایم۔ کے۔ سماج وادی جنتا دل اور بھارتیہ جنتا پارٹی ... "مداخلت" میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ اس خط کو بی۔ پی۔ سی۔ نے نشر کیا۔ وائس آف امریکہ نے نشر کیا اور دور درشن نے بھی نشر کیا۔ کیا منتری جی کو اس کی جانکاری ہے اور اگر جانکاری ہے تو اس سلسلہ میں منتری جی نے یونائیٹڈ نیشنس کو لکھت روپ میں کیا کارروائی کی ہے۔ یا کیا رکویسٹ کی ہے۔ وہ بتانا گوارا کریں گے۔ لکھت روپ میں انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ چونکہ سوال کا جواب دیا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنس

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

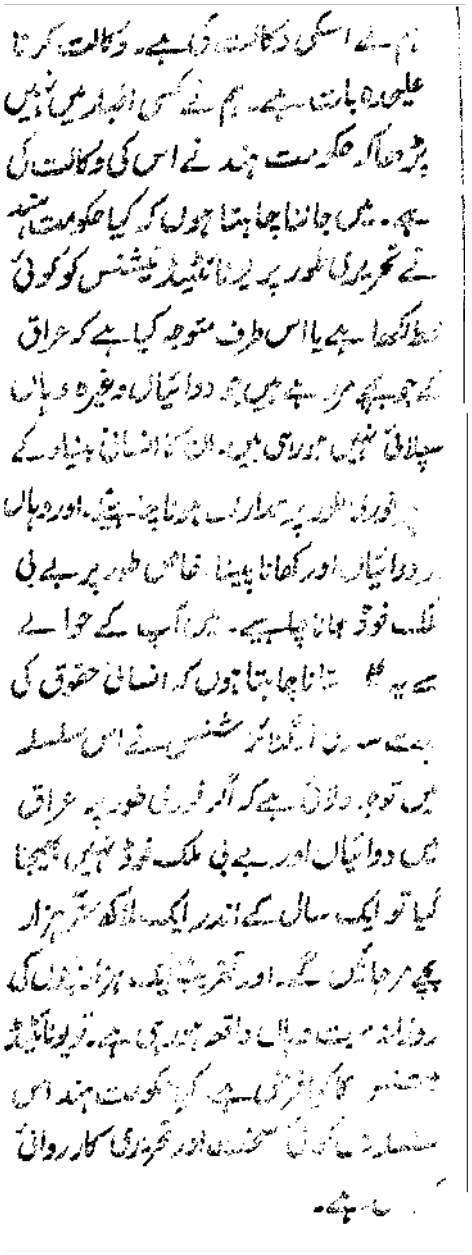

SHRI MADHAV SING SOLANKI : Sir, from the very outset of the conflict India has been concerned with the humanitarion aspect of this crisis including the suffering caused to the civilian population not only in Kuwait but also in Iraq.

With regard to the specific question of sanctions, we have consistently urged for the easing of embargo on the supply of essential needs and requirements of the prople of Iraq. I can show the hon. Members how many times and in what pressure India has represented the case for supplying medicines, food etc. to Iraqi population and also lifting of the embargo. At the time of adoption of Resolution 686 in March 1991 our permanent representative spoke in the Security Council about the havoc that sanctions were playing with Iraqi economy and with other economies. He said, "The people of Iraq certainly deserve relief.' At the time of adoption of Resolution 687 in April, 1991 our permanent representative has made a detailed statement about our concern for civilian suffering and advocated the easing of tension. It was largely as a result of India and other non-aligned countries that the Security Council devised a simplified procedure for facilitating import of urgent requirements as seen in the Resolution. Again in August, 1991 our representative stated in the Security Council, "The humanitarian situation in Iraq continues to be grim. My delegation supported the idea of oilsales from Iraq to finance in a certain measure its humantarian needs. The Security Council has an obligation to redress the plight of the innocent just as the international community as a whole.

Sir, on 26th September, 1991 when *I* myself addressed the General Assembly, I said in my speech in the United Nations Assembly itself, "The Gulf region still suffers from the residue of the War. The United Nations has the duty and the responsibility to exert all its energy to remove the suffering hunger and squalor left behind by the War." This is particularly true of the Iraqi civilian population whose misery is not lightened by the continuation of economic and trade sanctions Sir, as a result of India's effort-India led the non-aligned countries also for support in this case~ a proposal has been made on 9th December that essential commodities should be permitted to be exported to Iraq without requiring clearance from the Sanctions Committee. The proposal is under the consideration of the Security Council and our representative in the Security Council who is a member of the Security Council, with the support of the non-aligned countries, time and again, has again represented the case; that is why the sanctions had been eased *to* some extent and Iraq was permitted *to* sell oil so that from that revenue they could purchase food and medicines.

†Transliteration in Arabic Script.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : मोहतरिम वजीर ने जो जवाब दिया है, मुझे खुशी हुई कि हमारी हुकूमत ने इस सिलसिले में काम किये हैं लेकिन हमारे वजीर साहब ने यह जवाब नहीं दिया कि क्या उन्हें 51 मेम्बराने पार्लियामेंट के उस खत की कोई जानकारी है या नहीं है। अगर उसका जिक्र भी कर देते तो बड़ा बेहतर होता। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपने जो तमाम एफर्ट्स बताये हैं जो इराक को मेडिसिन्स और फूड सप्लाई करने के सिलसिले में आपने एकदामात किये हैं और बराबर एडवोकेट किया है और जिसकी कुछ मिसालें आपने पेश की हैं क्या उसके नतीजे में अब तक वाकई इराक को दवाइयां और बेबी मिल्क फूड पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? अगर पहुंचा है तो उसकी जानकारी यकीनन आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचा है तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि आप यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के मेम्बर हैं और एक अहम मेम्बर हैं, इतने रिजोल्यूशन पास होने के बावजूद और इतनी कोशिशों के बावजूद अगर इराक के अवाम तक, उनके बच्चों, बूढ़ों तक उनके बीमारों तक एनैसथीसिया तक नहीं पहुंच पा रहा है, दवाइयां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो यह किसका दबाव है? क्या मैं इस सिलसिले में यह पूछ सकता हूं मंत्री महोदय से कि अमरीका बराएरास्त इसमें मदाखलत कर रहा है और यूनाइटेड नेशन्ज के मुख्तलिफ मुल्कों पर प्रैशर डाल रहा है कि वह इराक के सिलसिले में अपनी आवाज को बुलंद न करें। क्या हुकूमत-ए-हिन्द के ऊपर भी इस तरह का कोई डायरेक्ट या इंडायरेक्ट प्रैशर अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से है? क्योंकि सारी दुनियां के अखबारों में यह इलजाम लगाया जाता रहा है कि इराक के सिलसिले में जो कुछ भी... (व्यवधान)

†شری محمد افضل عرف م۔ افضل: محترم وزیر نے جو جواب دیا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری حکومت نے اس سلسلہ میں کام کئے ہیں لیکن ہمارے وزیر صاحب نے یہ جواب نہیں دیا کہ کیا انہیں ۵۱ ممبران پارلیمنٹ کے اس خط کی کوئی جانکاری ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا ذکر بھی کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو تمام افرٹس بتائے ہیں جو عراق کو میڈیسنس اور فوڈ سپلائی کرنے کے سلسلہ میں آپ نے اقدامات کئے ہیں اور برابر ایڈوکیٹ کیا ہے۔ اور جس کی کچھ مثالیں آپ نے پیش کی ہیں۔ کیا اس کے نتیجہ میں اب تک واقعی عراق کو دوائیاں اور بے بی ملک فوڈ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ اگر پہنچا ہے تو اس کی جانکاری یقیناً آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر نہیں پہنچا ہے تو میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ یونائیٹڈ نیشنس کی سکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں۔ اور ایک اہم ممبر ہیں۔ اتنے ریزولیشن پاس ہونے کے باوجود اور اتنی کوششوں کے باوجود اگر عراق کے عوام تک ان کے بچوں اور بڑھوں تک ان کے بیماروں تک اینستھیسیا تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ دوائیاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ تو یہ کس کا دباؤ ہے۔ کیا میں اس سلسلہ میں

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

یہ پوچھ سکتا ہوں منتری مہودے سے کہ امریکہ اس میں براہ راست مداخلت کر رہا ہے اور یونائیٹیڈ نیشنس کے مختلف ملکوں پر پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ عراق کے سلسلہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ کیا حکومت ہند کے اوپر بھی اس طرح کا کوئی ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ پریشر امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ ساری دنیا کے اخباروں میں یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ عراق کے سلسلہ میں جو کچھ بھی... "مداخلت"...

MR. CHAIRMAN: He is asking whether America is putting pressure on you. That is all.

SHRI MADHAV SINH SOLANKI: Sir, absolutely no. There is no question of any pressure from America or from any other country. On the contrary, we are putting pressure on the Security Council to ease sanctions and India has arranged to send nearly 6284 tonnes of supplies-food, medicine, etc.-to Iraq which have already reached there. Government of India has financed these things. I may say that India does not lag behind in such humanitarian efforts and India is leading the non-aligned countries to see that sanctions are lifted and that in a more practical manner food, medicine, etc., reach Iraq.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : सभापति महोदय, इराक भारत का बहुत ही पुराना मित्र है और जो मित्र जरूरत में काम न आए वैसा मित्र क्या रहना । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा कि यह आर्थिक प्रतिबंध तो उन मुल्कों ने लगाया है जिन मुल्कों ने इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है । और भारत जो कि सर्वदा शांति का प्रतीक रहा है और ऐसे मौके में मदद के लिए आगे बढ़ कर मददगार रहा है, क्या भारत सरकार ने कोई योजना बनाई है जिसके माध्यम से, क्योंकि आयात और निर्यात अगर फायदे के लिए, मुनाफे के लिए किए जा रहे हों तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लग सकता है, पर अगर यह मानवाधिकार के तहत भेजे जा रहे हों तो मेरे ख्याल से उस पर प्रतिबंध नहीं लगता है? क्या भारत सरकार मुफ्त की दवाइयां, मुफ्त के बेबी फूड और मुफ्त के कपड़े वहां भेजने का कोई कार्यक्रम बना रहा है और साथ ही साथ गुट निरपेक्ष देशों में भारत एक अहम भूमिका निभाता रहा है, क्या भारत सरकार ने कोई ऐसी पहल की है कि गुट निरपेक्ष देशों को मिला कर एक ऐसी पूल बनाया जाए जो सारे देश दवाइयां इकट्ठी करके और बेबी फूड और मिल्क फूड इकट्ठा ईराक को मदद कर सके?

श्री माधव सिंह सोलंकी : माननीय सभापति जी, दुनिया के कई देश इराक की प्रजा को मदद कर रहे हैं, भारत भी इसमें पीछे नहीं हैं । अभी मैंने बताया कि भारत की ओर से 6,284 टन जिसमें शूगर, राइस, मैदा, आटा, मैडिसिन, मिल्क एंड बिस्किट्स... (**व्यवधान**) This year on the 9th of May the goods have reached there. और कोशिशें आज भी चल रही हैं । इसमें नान-गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशंज भी मदद कर रही हैं । सब मदद मिलेगी । हम तो असली सवाल यह उठाना चाहते हैं कि जो सैंक्शन्ज लगाए हैं वह ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ईज कर देने चाहिएं ताकि दुनिया से, भारत से चीजें इराक को जाकर मिलें ।

चौधरी हरि सिंह : मान्यवर, यह इराक के खिलाफ दुनियां की सब से बड़ी ताकतों ने हमला किया और इराक को तबाह कर दिया और मेरी जानकारी में यह है कि लगभग 20 हजार से ज्यादा बच्चे महज दवाइयों और उनका इलाज न मिलने की वजह से मर गए तो मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पहले लॉट में तो कुछ दवाइयां और खाने की चीजें और बेबी फूड वगैरह दिया, मेरा सीधा सवाल यह है कि वार खत्म होने के बाद से अब तक के पीरियड में कितने डाक्टर्ज, कितनी मैडिसिन्स, कितना फूड बच्चों की खुराक के लिए, और बच्चों के लिए स्पेशलि स्ट्स

†[]Traasliteration in Arable Script.

डाक्टर्ज जो होते हैं वह कितने इंडिया से भेजे गए हैं, नंबर एक ?

दूसरे, क्या वे अभी भी वहां काम कर रहे हैं या वापिस आ गए हैं ? तीसरे वहां बच्चों के मरने की और स्वस्थ होने की इस वक्त क्या अवस्था है, यह जानकारी भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा ?

SHRI MADHAV SINH SOLANKI: It would be difficult to estimate the number of civilian deaths as a direct result of the sanctions. "Lakhs of deaths" refferred to by certain people may not be correct. But the International Committee of the Red cross had sent a mission to Iraq in October, 1991. The report says that most medicines and medical supplies had run out. Only emergency operations and minor surgeries were being performed. The mission confirmed that the distress of the Irarqi population continues to grow for want of medicines, etc. So, it is difficult to establish the exact causes and linkages to the deaths, etc. and we cannot know the figures. But surely efforts to help Iraqi population are continuing not only by India but by other countries as well. At the moment 1 nave not got the details as to how many doctors are working in Iraq.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO : I would like to know from the hon. Minister whether the Indian citizens in Kuwait are facing the same problems as are faced by the Iraqi citizens, particularly those who have put up long service in Kuwait and who came out of Kuwait during the war. They have not been able to return there. Sir, they were neither invited by the Kuwaiti Government nor they were paid any compensation and their service also is not taken into account. May I know this from the hon. Minister—because Kuwait also was involved in the war—how Indian citizens are treated in Kuwait now ?

SHRI MADHAV SINH SOLANKI : Sir, the Indian citizens in Kuwait also had to suffer difficulties during the war. But today Kuwait is an independent and free country and having good relations with every country. The present question is with regard to. sanctions in Iraq. In Kuwait, there are no sanctions.

SHRI KAPIL VERMA : Sir, I am happy that the Government of India is making all-out efforts to get sanctions eased. I want to know from the hon. Minister, which are the countries in the Security Council who have opposed our move for easing the sanctions. Sir, the Iraqi Ambassador in India—the Minister has just now told that Iraq has been allowed to make purchases — held a press conference and openly offered to buy on the spot wheat, rice, tea, etc., on cash basis. I want to know from the hon. Minister what was the response and how much collection was there.

SHRI MADHAV SINH SOLANKI : Sir, it is reported that some of the Western countries are not very much in favour of making any major changes in the sanctions.

SHRI JAGESH DESAI : What about America ?

SHRI MADHAV SINH SOLANKI : Sir, UK, USA and France are against any major changes in the sanctions.

SHRI KAPIL VERMA : Sir, Iraqi Ambassador has offered to make on - the-spot purchases on cash basis as allowed by the security Council. Now the Iraqi Ambassador has offered to purchase it in India. I want to know whether we have received any response.

SHRI MADHAV SINH SOLANKI: Sir, the Security Council decided on 14th August, 1991, on easing of sanctions to enable Iraq to export oil to generations revenue upto 1.6 billion dollers. A part of the revenue can be put to use by Iraq for importing food stocks, medicines, etc. to meet the urgent humanitarian requirements. However, the resolutions laid down a number of terms and conditions. And Iraq has not up till now accepted these terms and conditions.

MR. CHAIRMAN : He wants to know; if it is willing to pay will you be able to give them goods ?

SHRI MADHAV SINH SOLANKI : We have to take the permission of the Sanctions Committee.

SHRI M. VINCENT: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the Minister whether it is a fact that the Indian Embassy building to Kuwait was damaged during the 1990 Gulf War. If BO, what

is the extent of loss of property and whether Indian property was damaged? I would also like to know what action was taken by the Indian Government to claim compensation. Whether the Govt. have asked the united Nations compensation Commission to pay compensation?

MR. CHAIRMAN: We are discussing about humanitarian aid and not about compensation.

श्री रफीक आलम : चेयरमेन सर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार क्या आइंदा इस सिलसिले में कोई कदम उठाने जा रही है, खासकर के दवाइयों के सिलसले में, खाने और कपड़े के सिलसिले में? चूंकि इराक हमारा दोस्त रहा है और हमेशा, कश्मीर के मसले में भी, इराक ने हमारा साथ दिया है तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी हर तरह की मदद करें। क्या भारत सरकार इस सिलसिले में कोई कार्यवाही करने जा रही है?

†شری رفیق عالم: چیرمین سر، میں منتری مہودیہ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار کیا اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے جا رہی ہے خاص کر دواؤں کے سلسلے میں۔ کھانے اور کپڑے کے سلسلے میں۔ چونکہ عراق ہمارا دوست رہا ہے اور ہمیشہ کشمیر کے مسئلے میں بھی عراق نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ہر طرح کی مدد کریں۔ کیا بھارت سرکار اس سلسلے میں کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے۔

SHRI MADHAV SINH SOLANKI: Sir, India's sympathies have always been with Iraqi population. We have been trying as far as practicable to help them. But it is also for Iraq to purchase food and medicine:. They are permitted to sell oil, from the revenue of which they can purchase food and medicines for their people. They have also to make efforts.

†[ ] Transliation in Arabic Script.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 343.

Planning Commission's concurrence on construction of National Highways

*343. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that concurance of Planning commission is being obtained in cases of new national highways, namely, (i) Chitradurga-Shimoga Mercara-Tellichery and (ii) Bangalore-Kanakpura-Mysore-Calicut; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No. Sir,

(b) Does not arise.

SHRI H. HANUMANTHAPPA : I remember very well, while discussing about the National Highway, the Road Development Plan of India had actually decided to construct 60000 kms. of national highway. It was decided to construct 3900 kms. of highway in Karnataka alone. Until today, only 1997 kms. have been constructed so far. From the reply of the Minister, I feel that the Surface Transport Ministry is actually sleeping and has not yet woken up from its slumber. Last week also, there was a question on this subject which was not reached. This week when the question comes, the Ministry comes out with a stock reply, "No", Sir, 'Does not arise'. My question is: whether the concurrence of the Planning commission is being sought. They say, 'no'. I have a copy of the letter of his predecessor to the Chief Minister of Karnataka wherein he has written—this is a letter dated 20th June, 1990. I may be permitted to quote, Sir. "You would be happy to note that we have already obtained the concurrence of the Planning Commission. . . . (*Interruptions*)

SHRI JAGESH DESAI: Sir, what is this. . . . (*Interruptions*)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, the Minister is giving a wrong answer. The Planning Commission has already given its concurrence. His predecessor has written a letter to the Chief Minister Mr. Veerendra Patil to this effect. In view of this, will the Minister correct his answer. . . . (*Interruptions*)

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, on 12th April, 1990, this question had been raised in Lok Sabha and we had said that it was under active consideration. It is also true that the Planning commission